GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

दौसा जिले के वित्तीय समावेशन पर सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों के प्रभाव पर एक अध्ययन

सुरेंद्र कुमार शर्मा, पवन कुमार भूरा

सहायक प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग
श्याम लाल कॉलेज (सांध्य)
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत
ईमेल- surendrasharma68910@gmail.com

सहायक प्रोफेसर
वाणिज्य विभाग
श्याम लाल कॉलेज (सांध्य)
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत
ईमेल- dr.41bh21@gmail.com

संक्षेप

इस अध्ययन का उद्देश्य राजस्थान के दौसा जिले में वित्तीय समावेशन(सामान्यत: वित्तीय समावेशन जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच बैंकिंग गतिविधियाँ के प्रसार से संबंधित है।) पर जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक कारकों के प्रभावों की जांच करना है। प्राथमिक और द्वितीयक समंक के संयोजन के माध्यम से, अध्ययन के द्वारा 2010 से 2020 तक जानकारी एकत्र की गई है। जिले को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है और प्रत्येक श्रेणी से 100 नमूनों में काई-वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न जनसांख्यिकीय चर और वित्तीय समावेशन के बीच संबंध को मापना था। अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा और आय का लोगों की वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरूकता पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, लिंग(जेंडर) का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अध्ययन में यह भी कहा गया कि जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक कारकों का वित्तीय समावेशन पर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन ने संकेत दिया कि लेख में उल्लिखित विभिन्न कारकों का अनुसरण करने से जिले में वित्तीय समावेशन हासिल करने में मदद मिल सकती है।

मुख्य शब्द: *वित्तीय समावेशन, सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन, वित्तीय साक्षरता*

परिचय

सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में वित्तीय समावेशन की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों को उचित वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच प्राप्त हो। यह विनियमित संस्थागत निकाय के एक तंत्र की स्थापना के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय समावेशन के दो अर्थात पूर्ति और मांग पक्ष हैं। मांग पक्ष का संबंध कम आय वाले परिवारों और परिसंपत्ति होल्डिंग्स की कमी से है। दूसरी ओर, पूर्ति पक्ष कमजोर और गरीबों तक पहुंचने के बैंकों के प्रयासों से संबंधित है। ये मुद्दे महंगे हैं और इनमें वित्तीय साक्षरता की कमी है। किसी क्षेत्र के वित्तीय समावेशन को प्रभावित करने वाले विभिन्न बाहरी कारकों को क्षेत्र की जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं द्वारा भी ध्यान में रखा जाता है। इन कारकों में लिंग(जेंडर), आय, शिक्षा और व्यवसाय स्तर शामिल हैं। दूसरी ओर, ये कारक किसी क्षेत्र के वित्तीय समावेशन को

https://www.gapbhasha.org/

नकारात्मक या सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य दौसा जिले के वित्तीय समावेशन में जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक कारकों की भूमिका की जांच करना है।

साहित्य समीक्षा:-

सरमा और पेस (2011) ने विभिन्न कारकों की जांच की जो वित्तीय समावेशन को प्रभावित कर सकते हैं। परिणामों से पता चला कि कुछ सामाजिक-आर्थिक कारकों, जैसे उच्च आय स्तर और साक्षरता, का इस स्थिति के साथ सकारात्मक संबंध है। दूसरी ओर, बेरोजगारी और आय असमानता जैसे अन्य मुद्दों में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं दिखा।

बिस्वास और गुप्ता (2012) इस अध्ययन का लक्ष्य यह निर्धारित करना था कि क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता का स्तर कुछ जनसांख्यिकीय कारकों जैसे घरेलू आय, व्यवसाय और शैक्षिक पृष्ठभूमि के समावेश से प्रभावित होता है। परिणामों से पता चला कि ग्रामीण उत्तरदाताओं की वित्तीय साक्षरता शहरी उत्तरदाताओं की तुलना में काफी कम थी। पेपर में कहा गया है कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता एक-दूसरे के पूरक हैं। उच्च स्तर की वित्तीय साक्षरता होने से लोगों को अच्छे निर्णय लेने और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँचने में मदद मिल सकती है।

विजयकुमार और कृष्णकुमार (2013) ने केरल के पांडिचेरी जिले के तीन गांवों में बैंकिंग सेवाओं का विश्लेषण किया: एरियानकुप्पम, कलापेट और वीरमपट्टनम। इसमें वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए बैंकों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर भी गौर किया गया। अध्ययन से पता चला कि आयु, शिक्षा और व्यवसाय जैसे जनसांख्यिकीय कारकों का समुदाय के वित्तीय समावेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अध्ययन से पता चला कि जनसंख्या के महिला वर्ग का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि जनसांख्यिकीय कारकों के उपयोग के माध्यम से इस क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की प्रचार गतिविधियाँ की जानी चाहिए।

सेल्वाकुमार, जैकब और सत्यलक्ष्मी (2015), अध्ययन में उत्तरदाताओं की विभिन्न विशेषताओं और वित्तीय समावेशन के बारे में उनकी अपेक्षा के स्तर के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। हालाँकि, आयु, आय और पारिवारिक स्थिति वित्तीय समावेशन की अपेक्षा से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी। अध्ययन ने संकेत दिया कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का विस्तार किया गया तो भारत की वृद्धि अधिक समावेशी होगी।

कंडारी, बहुगुणा और सालगोत्रा (2020) ने जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक तत्वों और वित्तीय समावेशन के बीच संबंध की जांच की। विचार किए गए कुछ संकेतकों में बैंक खाता स्वामित्व, मोबाइल बैंकिंग उपयोग और क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाना शामिल है। इससे पता चला कि कुछ सामाजिक-आर्थिक कारकों ने क्षेत्र के वित्तीय समावेशन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अध्ययन में राज्य के पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों की वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया। इससे पता चला कि इन व्यक्तियों की वित्तीय साक्षरता में वृद्धि से बैंक खाता खोलने और मोबाइल बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने की संभावना काफी बढ़ गई है। इसने यह भी सुझाव दिया कि महिलाओं और निचली जाति के व्यक्तियों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। यह उन सेवाओं के वितरण के माध्यम से किया जा सकता है जो राज्य के संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आय बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :-

- इस अध्ययन का लक्ष्य उन कारकों की पहचान करना है जो राजस्थान के दौसा जिले में लोगों के वित्तीय समावेशन को प्रभावित करते हैं।
- इस अध्ययन का लक्ष्य वित्तीय समावेशन पर जनसांख्यिकीय कारकों के प्रभावों का विश्लेषण करना है।
- इसका उद्देश्य उन कारकों की पहचान करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कम वित्तीय समावेशन दर में योगदान करते हैं।

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

- अध्ययन जिले के वित्तीय समावेशन में सुधार के तरीकों पर भी सिफारिशें प्रदान करेगा।

अध्ययन की परिकल्पना

H_0: जनसांख्यिकीय चर {लिंग(जेंडर), व्यवसाय शिक्षा, आय} और वित्तीय सेवाओं (वित्तीय समावेशन) के बारे में जागरूकता के बीच कोई संबंध नहीं है।

H_1: जनसांख्यिकीय चर {लिंग(जेंडर), व्यवसाय, शिक्षा, आय} और वित्तीय सेवाओं (वित्तीय समावेशन) के बारे में जागरूकता के बीच एक संबंध है।

अनुसंधान प्राविधि

वर्तमान शोध में दौसा जिले में वित्तीय समावेशन की स्थिति की जांच करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक समंक को सुनिश्चित किया गया है। एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्र किया गया और 2010 से 2020 तक के समंक का अध्ययन किया गया है। अध्ययन किए गए जिले को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, और प्रत्येक श्रेणी से यादृच्छिक रूप से 100-100 नमूने चुने गए हैं। समंक सारणीकरण के बाद परिकल्पना परीक्षण के लिए काई-वर्ग परीक्षण का उपयोग किया गया है।

तालिका **1**

नमूने का गठन

क्र.सं. समूह	नमूनों का चयन	गांव	नमूना आकार
1 अ	ऐसे गांव जहां कोई बैंक नहीं है	बड़ा-बुजुर्ग,खानपुर,गाजीपुर, जटवारा	100
2 ब	ऐसे गांव जहां केवल सहकारी और ग्रामीण बैंक मौजूद हैं	सांथा, जीरोटा-कला	100
3 स	ऐसे गांव जहां वाणिज्यिक, सहकारी और ग्रामीण बैंक मौजूद हैं	महवा, बांदीकुई, मंडावर	100
4 द	टाउनशिप - जहां विभिन्न बैंक मौजूद हों	दौसा, लालसोट	100

Sources:- 1.http://slbcrajasthan.in , 2. Census of India 2011, Rajasthan, series- 09 ,Part XII-A.

तालिका **2**

प्रतिवादियों की जनसांख्यिकी-रूपरेखा

जनसांख्यिकी-रूपरेखा	चर	समूह अ	समूह ब	समूह स	समूह द	आवृत्ति	प्रतिशत
लिंग(जेंडर)	पुरुष महिला	60 40	63 37	56 44	61 39	241 160	60 40
शिक्षा	निरक्षर 10वीं से नीचे माध्यमिक उच्च माध्यमिक	08 26 19 09	07 28 15 12	01 09 18 26	- 01 - 24	16 64 52 71	4 16 13 17.75

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

	स्नातक स्नातकोत्तर	34 04	32 06	40 06	60 15	166 31	41.50 7.75
व्यवसाय	कृषक सेवा स्व: व्यवसाय कृषि-श्रम अन्य	52 05 25 10 08	56 06 18 08 12	46 14 28 05 07	30 15 49 01 05	184 40 120 24 32	46 10 30 6 8
आय	25000/- से नीचे 25000/- से 50,000 50,000/- से 75000/- 75000/- से ऊपर	34 20 21 25	45 20 14 21	03 11 39 47	03 05 41 51	85 56 115 144	21.25 14 28.75 36

तालिका 2 की व्याख्या :-

ऊपर दी गई तालिका 400 प्रतिवादियों का नमूना आकार दिखाती है, जिसमें 40 प्रतिशत महिलाएं और 60 प्रतिशत पुरुष हैं। प्रतिवादियों की शिक्षा स्थिति के अनुसार, 16 प्रतिशत 10वीं से नीचे हैं, और 4 प्रतिशत निरक्षर हैं। उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण करने वालों में, 17.75 प्रतिशत वरिष्ठ हैं, 41.54 प्रतिशत स्नातक हैं, और 7.75 प्रतिशत स्नातकोत्तर हैं। व्यवसाय के संदर्भ में, प्रतिवादियों में किसानों की संख्या अधिकतम 46 प्रतिशत है। दूसरी ओर, उनमें से 30 प्रतिशत का अपना व्यवसाय है, जबकि 10 प्रतिशत सेवा में हैं। 8 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं, और 6 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। प्रतिवादियों की आय की स्थिति से पता चलता है कि उनमें से लगभग 21.25 प्रतिशत 25 हजार से नीचे की श्रेणी में हैं, जबकि 14 प्रतिशत 25 से 50 हजार की श्रेणी में हैं।

काई-वर्ग विश्लेषण :-

परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए चरों पर काई-वर्ग परीक्षण लागू किया गया था, संबंधित तालिकाएँ नीचे दी गई हैं-

1. वित्तीय सेवाओं के बारे में लिंग(जेंडर)/जागरूकता
2. वित्तीय सेवाओं के बारे में शिक्षा/जागरूकता
3. वित्तीय सेवाओं के बारे में आय/ जागरूकता

तालिका **3**

अवलोकित आवृत्तियां **(F_0)**

लिंग(जेंडर)/जागरूकता	जागरूक	जागरूक नहीं	कुल
पुरुष	231	09	240
महिला	147	13	160
कुल	**378**	**22**	**400**

तालिका **4**

प्रत्याशित आवृत्तियां **(F_e)**

लिंग(जेंडर)/जागरूकता	जागरूक	जागरूक नहीं	कुल
पुरुष	227	13	240
महिला	151	09	160

https://www.gapbhasha.org/

कुल	**378**	**22**	**400**

तालिका **5**

काई-वर्ग तालिका

F_0	F_e	$F_0 - F_e$	$(F_0 - F_e)^2$	$(F_0 - F_e)^2/F_e$
231	227	4	16	.070
147	151	-4	16	.108
09	13	-4	16	1.230
13	09	4	16	1.777
			कुल	3.185

स्वातंत्र्यांश- (2 - 1) (2 - 1) = 1

5% सार्थकता के स्तर पर काई-वर्ग तालिका मान = 3.841

काई-वर्ग तालिका का परिकलित मान = 3.185

H0 स्वीकृत है; जो स्पष्ट करता है कि वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता पर लिंग(जेंडर) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका **6**

अवलोकित आवृत्तियां **(F_0)**

शिक्षा/जागरूकता	जागरूक	जागरूक नहीं	कुल
निरक्षर	07	09	16
10वीं से नीचे	61	03	64
माध्यमिक	50	02	52
उच्च माध्यमिक	69	02	71
स्नातक	161	05	166
स्नातकोत्तर	30	01	31
कुल	**378**	**22**	**400**

तालिका **7**

प्रत्याशित आवृत्तियां **(F_e)**

शिक्षा/जागरूकता	जागरूक	जागरूक नहीं	कुल
निरक्षर	15.12	.88	16
10वीं से नीचे	60.48	3.52	64
माध्यमिक	49.14	2.86	52
उच्च माध्यमिक	67.09	3.91	71
स्नातक	156.87	9.13	166
स्नातकोत्तर	29.30	1.70	31
कुल	**378**	**22**	**400**

तालिका **8**

काई-वर्ग तालिका

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

F_0	F_e	$F_0 - F_e$	$(F_0 - F_e)^2$	$(F_0 - F_e)^2/F_e$
07	15.12	-8.12	65.93	4.36
61	60.48	.52	.27	.004
50	49.14	.86	.74	.015
69	67.09	1.91	3.65	.054
161	156.87	4.13	17.06	.109
30	29.30	.70	.49	.017
09	.88	8.12	65.93	74.92
03	3.52	-.52	.27	.077
02	2.86	-.86	.74	.259
02	3.91	-1.91	3.65	.933
05	9.13	-4.13	17.06	1.868
01	1.70	-.70	.49	.288
			Total	82.904

स्वातंत्र्यांश- (2 - 1) (6 - 1) = 1 x 5 = 5

5% सार्थकता के स्तर पर काई-वर्ग तालिका मान = 11.10

काई-वर्ग तालिका का परिकलित मान = 82.904

H0 अस्वीकृत है; जो स्पष्ट करता है कि शिक्षा का वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता पर प्रभाव पड़ता है।

तालिका **9**

अवलोकित आवृतियां **(F_0)**

आय/जागरूकता	जागरूक	जागरूक नहीं	कुल
25,000 से नीचे	74	11	85
25000 से 50000	48	08	56
50000 से 75000	109	06	115
75000 से ऊपर	138	06	144
कुल	**378**	**22**	**400**

तालिका **10**

प्रत्याशित आवृतियां **(F_e)**

आय/जागरूकता	जागरूक	जागरूक नहीं	कुल
25,000 से नीचे	80	5	85
25000 से 50000	53	3	56
50000 से 75000	109	6	115
75000 से ऊपर	136	8	144
कुल	**378**	**22**	**400**

तालिका **11**

काई-वर्ग तालिका

F_0	F_e	$F_0 - F_e$	$(F_0 - F_e)^2$	$(F_0 - F_e)^2/F_e$
74	80	-6	36	.45
48	53	-5	25	.47

https://www.gapbhasha.org/

109	109	0	0	0
138	136	2	4	.03
11	5	6	36	7.2
08	3	5	25	8.3
06	6	0	0	0
06	8	-2	4	.5
			Total	16.95

स्वातंत्र्यांश- (2 - 1) (4 - 1) = 1 x 3 = 3
5% सार्थकता के स्तर पर कई वर्ग तालिका मान = 7.81
काई-वर्ग तालिका का परिकलित मान = 16.95
H_0 अस्वीकृत है; जो स्पष्ट करता है कि आय का वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता पर प्रभाव पड़ता है।

सुझाव

दौसा जिले में ग्रामीण लोगों की वित्तीय समावेशन स्थिति में सुधार के लिए अध्ययन के सुझाव हैं-

- ग्रामीण और बैंक रहित क्षेत्रों में कमजोर आबादी की वित्तीय सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंकों को अपने परिचालन का विस्तार करना चाहिए। उन्हें इन समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित उत्पाद और सेवाएं भी विकसित करनी चाहिए।
- दूरदराज के स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को व्यक्तियों को संवाददाता के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी है। ये व्यक्ति अपने ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होने के अलावा, ये संवाददाता वित्तीय उत्पादों और ऋण प्रबंधन के बारे में जागरूकता भी बढ़ाते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी, वित्तीय समावेशन की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, बीसी को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, इन मुद्दों को संबोधित करना और वित्तीय समावेशन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। आरबीआई के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है जो बीसी के रूप में कार्य कर सकते हैं। हालाँकि, इसमें आंशिक रूप से विकलांग लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें नौकरी मिल सके।
- जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता की कमी को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लोगों की वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने के उद्देश्य से की जाने वाली विभिन्न पहलों को लागत प्रभावी तरीके से डिजाइन और कार्यान्वित किया जाए। इसे प्राप्त करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की विभिन्न गतिविधियों को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और सामाजिक उद्यमों के साथ जोड़ना है। इससे उन्हें मूल्य श्रृंखला की गहरी समझ विकसित करने और उनके संचालन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- एक अध्ययन के अनुसार, जिले में पीएमजेडीवाई कार्यक्रम के तहत पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा बैंक खाते खोलने की अधिक संभावना है। इससे पता चलता है कि वित्तीय समावेशन में लिंग कोई मायने नहीं रखता। महिलाएं अपने बच्चों और परिवारों को शिक्षित करके वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से समावेशी बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता है। यह विभिन्न पहलों जैसे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है जो विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और बैंकों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इनके अलावा, महिलाओं को अपने समुदायों में स्वयं जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।
- अध्ययनों के अनुसार, उच्च आय स्तर वाले देशों में वित्तीय समावेशन की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के

https://www.gapbhasha.org/

लिए, विकासशील देशों में, वित्त तक पहुंच गरीब व्यक्तियों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकती है। ऐसा इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर स्थापित करके किया जा सकता है।

- आंकड़ों के मुताबिक, देश की करीब 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम उम्र की है. यह हमारी युवा पीढ़ी है, जिसे ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है। इस वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल विकास और शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकता है। इसमें निवेश करने से दीर्घकालिक वित्तीय समावेशन और लाभ मिल सकता है।

निष्कर्ष

अध्ययन से संकेत मिलता है कि वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए बैंकिंग प्रणाली और सरकार के प्रयासों के बावजूद, जिले को पूर्ण वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इसे प्राप्त करने का एक तरीका वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से है जो विशिष्ट समूहों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक समावेशी बनाने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकार को युवाओं को स्व-रोज़गार बनने और देश के वित्तीय समावेशन में योगदान देने में मदद करने के लिए वित्तीय और मानव संसाधन प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने में सक्षम लोगों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सन्दर्भ

[1] आशिमा थापर (2013)। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैंगमेंट रिसर्च, वॉल्यूम। 3 नंबर 6; जून 2013

[2] भूषण, पी (2014)। वित्तीय साक्षरता और वेतनभोगी व्यक्ति के निवेश व्यवहार के बीच संबंध, जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस रिसर्च, वॉल्यूम। 3, 82-87.

[3] बिस्वास, शुभ्रा और गुप्ता, अरिंदम (2012)। वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता: पश्चिम बंगाल राज्य में चयनित शहरी क्षेत्रों के बीच उनके अंतर्संबंध में एक तुलनात्मक अध्ययन। आईओएसआर जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, 67-72।

[4] चट्टोपाध्याय, एस.के. (2011). भारत में वित्तीय समावेशन: पश्चिम बंगाल का केस अध्ययन। आर.बी.जे. वर्किंग पेपर सीरीज: 8/2011.1.

[5] गर्ग, बी. (2014)। वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास, रिसर्च जर्नल ऑफ कॉमर्स, 2(1), 1-6।

[6] गुप्ता, पी. और सिंह, बी. (2013)। भारत में वित्तीय समावेशन में साक्षरता स्तर की भूमिका: अनुभवजन्य साक्ष्य, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, 1(3), 272-276।

[7] कृष्णकुमार, आर. और विजयकुमल, एल. (2013)। वित्तीय समावेशन: एक जनसांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट रिसर्च खंड 5, अंक 12, पीपी 3835-3837, दिसंबर 2013।

[8] मुरारी, के. और डिडवानिया, एम. (2010)। वित्तीय समावेशन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन: भारत रहस्योद्घाटन के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, के.पी.बी. का शोध जर्नल। हिंदुजा कॉलेज, III. 60-72

[9] सरमा, एम. और पेस, जे. (2011)। वित्तीय समावेशन और विकास, जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 23, 613-628

[10] सेल्वाकुमार, एम., मथन, जैकब और सत्यलक्ष्मी वी. (2015.)। वित्तीय समावेशन की ओर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य, आर्थिक और सामाजिक जर्नल हालांकि वॉल्यूम। 2, अंक-2.

[11] स्वामी, वी. (2014)। वित्तीय समावेशन, लिंग आयाम, और गरीब परिवारों पर आर्थिक प्रभाव, विश्व विकास, 56, 1-15।

[12] .http://slbcrajasthan.in

[13] भारत की जनगणना 2011, राजस्थान, श्रृंखला-09, भाग XII-ए

https://www.gapbhasha.org/